

Q. what is public debt? critically examine the various method of repayment of public debt.

Ans → सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा आय प्राप्त करने का एक साधन है। सार्वजनिक ऋण उस ऋण को कहते हैं जिसे कि राज्य अपनी प्रजा से अथवा उन व्यक्तियों से या उसके नागरिकों से लेता है। सरकार जब उधार लेती है तो उससे लोक ऋण का जन्म होता है। सरकार देश के अन्दर भी ऋण ले सकती है और बाहर से अथवा दोनों जगहों से भी। आमतौर पर सरकार लोक ऋण बाण्ड के रूप में होता है। इन बाण्डों में सरकार यह वादा करती है कि वह निर्धारित समय में मूलधन साहित्य ध्याज की भी अदायगी करेगी।

जब कभी सरकार को आय से अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है तो उसे ऋण की व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार जो ऋण प्राप्त करती है उसे एक निश्चित अवधि के बाद उसका ध्याज साहित्य भुगतान करना होता है। Adam Smith के अनुसार "सार्वजनिक ऋण से कुछ खर्च फिजूलखर्ची जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं" परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार सार्वजनिक ऋण विकास के मार्ग को प्रभावित करता है। यह अल्पविकसित देशों को ऋण प्रदान करता है जिससे वह अपना विकास करता है तथा वह आपदा आने पर भी ऋण लेता है। अल्पविकसित देशों के विकास में सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्पविकसित देश अन्य विकसित देशों से ऋण लेकर अपना विकास करता है।

सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के मुख्य तरीका निम्नलिखित हैं →

(1) ऋण-नकार (Debt Repudiation) : → इस रीति के अन्तर्गत सरकार ऋण का भुगतान करने से इन्कार कर देती है और इस तरह स्वयं की ऋण के भार से मुक्त कर लेती है। सरकार नकार की नीति आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ऋणों के संबंध में अपना सकती है।

सन 1917 ई. में सौविधायक सरकार द्वारा ऐसा किया गया था जबकि उसने जार कालीन ऋणों को अदा करने से मना कर दिया था। U.S.A. के कुछ ब्राह्मणों ने भी 1861-65 के गृह युद्ध के पूर्व ऐसा ही किया जम्मा था। उन्होंने अंग्रेज नागरिकों से लिए गए ऋणों की उदात्तगी से इन्कार कर दिया था।

यह नीति देखने से आसान लगती है पर यह एक अनैतिक तथा बेईमानीपूर्ण पग माना जाता है।

(2) वार्षिक वृत्ति (Terminal Amorty) : → इस रीति के अन्तर्गत सरकार दीर्घकालीन ऋण का भुगतान वार्षिक किस्तों के रूप में करती है। इस रीति द्वारा सरकार पर धीरे-धीरे ऋण का दायित्व कम होता चला जाता है तथा भुगतान की अंतिम तिथि पर एकदम समस्त ऋण का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

(3) ऋण परिवर्तन (Loan Conversion) : → ऋण की बढ़ती का अर्थ है पुराने ऋण का नये ऋण में परिवर्तन। इस रीति के अन्तर्गत, ऋण की वास्तविक उदात्तगी नहीं की जाती, बल्कि ऋण

ऋण का केवल रूप बदल दिया जाता है। ऋण बदली की प्रक्रिया से मतलब होता है ऊंची व्याज दर वाले ऋण को कम व्याज-दर वाले ऋण में परिवर्तन करना।

(4) **ऋण परिभाषन कोष (Sinking Fund):** → इस रीति के अनुसार सरकार एक कोष की स्थापना कर लेती है तथा इस कोष में सरकार प्रतिवर्ष इतनी रकम डालती रहती है कि निश्चित तिथि पर व्याज सहित मूलधन का भुगतान सरलता पूर्वक किया जा सके। इस रीति के अनुसार सरकार दो तरह से धन एकत्रित करती है-

(1) अपनी वार्षिक आय में से कुछ रकम बचाकर इस कोष में जमा करती है या ऋण लेकर इस कोष में जमा करती है।

J. K. Mehta ने लिखा है ऋण परिभाषन कोष की पद्धति एक सर्वोत्तम तरीका है। यह एक क्रमबद्ध प्रणाली है तथा कोई भी दूसरे किसी भी विशेष ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में समाभोजित कर सकता है।

(5.) **क्रमानुसार भुगतान (Payment by Serial Number)**  
 → ऋणभुगतान की इस रीति में सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करती है कि जारी किए गए बॉन्ड्स में से कुछ को परिपक्वता अवधि प्रतिवर्ष पूरी हो जाए। इस रीति में ऋण का एक भाग प्रतिवर्ष चुकता कर दिया जाता है।

(6) **लाटरी द्वारा भुगतान (Payment by Lottery):** → यह रीति भी क्रमानुसार भुगतान का ही एक संशोधित रूप है। अन्तर केवल इतना ही है कि इस रीति में बॉन्ड्स की सरप्ला परामर्श में

क्रमानुसार निश्चित नहीं की जाती बल्कि  
लॉर्डरी द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका सबसे  
बड़ा अवशुण यह है कि इससे विनियोजकों की  
रूयण वापस मिलने के निश्चित समय  
पता नहीं रहता है।

7) **रूयण का पुनःशोधन (Refunding of Loan):** →  
इस रीति के अन्तर्गत सरकार नया रूयण  
लेकर पुराने रूयण का भुगतान करती है। आधिकार  
सरकार ऐसा तभी करती है जबकि उस पर रूयण का  
भार बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार पुनः शोधन  
रूयण परिवर्तन से ही मिलता जुलता है पर इस दोनों  
में अन्तर है।

8) **बजट की बचत का उपयोग:** → सरकार अपने  
बजट में व्यय को आय की तुलना में कम रखकर  
तथा इस तरह बचत करके उसका उपयोग रूयण  
भुगतान में करती है। वास्तव में यह रूयण शोधन  
का पुराना तरीका है। वर्तमान भुग में सरकार  
का कार्य इतना व्यापक हो गया है कि उसे  
बजट की बचत के अपेक्षा धार के बजट  
बनाने पड़ते हैं, इस रीति का कोई महत्व नहीं है।

9) **पूँजी कर:** → पूँजी-कर अल्पार्थ रूयण भार को कम  
करने में बहुत लाभकारी सिद्ध हो  
सकता है। जब सरकार विभिन्न प्रकार  
के कर लगाने में स्वयं की असमर्थ  
पानी है तो उस समय सरकार को  
पूँजी कर लगाने की नीति अधिक  
सहायक साबित होती है।

DATE

DATE

--	--	--	--	--	--	--	--

निष्कर्षतः उपर्युक्त सभी उद्धरण  
 ग्रन्थ के पुनर्भुगतान के तरीके हैं। जिनमें  
 लखनौ - बँकारा तरीका ग्रन्थ निषेध है। बाकि  
 लखनौ - डोक - डोक ही Proff. Pw + 07 के अनुसार  
 " सम्पूर्ण वाद विवाद के बीच मरा अपना  
 मान है कि ग्रन्थ को निबताने के हेतु  
 पूजा कर अपने गुणों के कारण लखनौ  
 अच्छी नीति है। "